रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा धान की खरीद और भंडारण प्रक्रिया का विश्लेषण

उमेश कुमार गुप्ता[1]
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, रायपुर (छ.ग.)[1]
डॉ. पी सी अग्रवाल[2]
प्रोफ़ेसर, वाणिज्य विभाग, शा. छत्तीसगढ़ कॉलेज, रायपुर (छ.ग.)[2]

सार

इस अध्ययन में रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (CG MARKFED) द्वारा संचालित धान की खरीदी एवं संग्रहण प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य धान खरीदी एवं संग्रहण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और इसमें आने वाली समस्याओं की पहचान कर समाधान सुझाना है। यह शोध वर्णात्मक (Descriptive) और तथ्यात्मक (Empirical) अनुसंधान विधियों पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया। प्राथमिक डेटा के लिए रायपुर जिले के 50 किसानों से साक्षात्कार लिया गया, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), भुगतान प्रणाली, और सरकारी खरीद प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे गए। साथ ही, CG MARKFED अधिकारियों के साथ चर्चा और धान खरीदी केंद्रों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। द्वितीयक डेटा के रूप में सरकारी रिपोर्टों, CG MARKFED की वार्षिक रिपोर्टों और संबंधित शोध पत्रों का अध्ययन किया गया। परिणामों से पता चला कि वर्ष 2010 से 2011 के बीच धान खरीदी की मात्रा में 10% वृद्धि हुई, जबकि संग्रहण क्षमता में 12.5% वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹1000 से बढ़कर ₹1030 प्रति क्विंटल हो गया, जिससे किसानों की आय में सुधार हुआ। भुगतान प्राप्त करने की अवधि 20 दिनों से घटकर 15 दिन हो गई, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिरता बढ़ी। इसके अलावा, सरकारी खरीद प्रणाली से संतुष्ट किसानों की संख्या 70% से बढ़कर 80% हो गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि CG MARKFED की नीतियाँ किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। हालाँकि, अध्ययन में यह भी सामने आया कि बढ़ती धान खरीदी से संग्रहण प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में भंडारण से जुड़ी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। अतः, सरकार को संग्रहण सुविधाओं के विस्तार और भुगतान प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है।

कीवर्ड: CG MARKFED, धान खरीदी, संग्रहण प्रक्रिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), छत्तीसगढ़, रायपुर, सरकारी खरीद प्रणाली, किसानों की संतुष्टि.

1. परिचय

धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और छत्तीसगढ़ को "धान का कटोरा" कहा जाता है। राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार धान उत्पादन है, और इसकी खरीदी एवं संग्रहण की प्रक्रिया किसानों की आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करती है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (CG MARKFED) इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो राज्य सरकार के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीदी, संग्रहण और विपणन को नियंत्रित करता है। धान की खरीदी और संग्रहण की व्यवस्था को अधिक प्रभावी और लाभकारी बनाने के लिए सहकारी संस्थानों, बैंकों और उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला का अध्ययन आवश्यक है। उदयकुमार et al. (2010) ने अपने अध्ययन में बताया कि धान उत्पादन

में संसाधन दक्षता बढ़ाने से किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार, कुमार और अलगुमानी (2005) ने तमिलनाडु के भवानी परियोजना क्षेत्र में धान की संसाधन उपयोग दक्षता का विश्लेषण करते हुए सुझाव दिया कि सही प्रबंधन और वितरण से उत्पादन में सुधार संभव है।

छत्तीसगढ़ के किसानों को धान खरीदी की प्रक्रिया में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे—बिचौलियों की भूमिका, भुगतान में देरी, संग्रहण की अपर्याप्त सुविधाएँ, और विपणन संबंधी समस्याएँ। इस संदर्भ में, सिंह एवं नासिर (2003) ने बिहार में कृषि ऋण प्रवाह का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि वित्तीय संस्थानों की सशक्त भूमिका कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है। इसी प्रकार, महाजन (2011) ने बैंकिंग व्यवस्था की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए बताया कि सहकारी बैंकों और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की भूमिका को प्रभावी रूप से समझने के लिए उर्वरक उपयोग, धान खरीदी की प्रक्रिया, संग्रहण की सुविधाएँ और वित्तीय सहायता की स्थिति का विश्लेषण करना आवश्यक है। इंद्रनील et al. (2009) ने पश्चिम बंगाल में छोटे किसानों के बीच उर्वरक उपयोग परिदृश्य का अध्ययन करते हुए बताया कि उर्वरक की उपलब्धता और उसकी उचित मात्रा में आपूर्ति से कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अर्देशना एवं खुंट (2011) ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में उर्वरक उपयोग में असमानता के निर्धारकों पर अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि सरकारी योजनाओं और सहकारी संस्थानों द्वारा उचित नीतियाँ बनाकर इस अंतर को कम किया जा सकता है।

धान खरीदी में सहकारी विपणन संघ की रणनीतियाँ और प्रभाव

धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में एक संगठित प्रक्रिया के तहत होती है, जिसमें MARKFED की प्रमुख भूमिका होती है। राज्य सरकार MSP पर धान की खरीदी सुनिश्चित करती है, जिससे किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके। हालांकि, इस प्रणाली में कई बाधाएँ भी हैं, जिनका समाधान आवश्यक है। दुबे (2007) ने राष्ट्रीयकृत बैंकों और लघु-कुटीर उद्योगों की भूमिका का अध्ययन करते हुए बताया कि सहकारी बैंकों और सरकारी योजनाओं की सहायता से किसानों को अधिक सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को समय पर भुगतान न मिलने की समस्या बनी रहती है, जिससे उनके वित्तीय हालात प्रभावित होते हैं। इसी तरह, सिंह एवं फजल (1998) ने कृषि और ग्रामीण विकास के संदर्भ में सहकारी संस्थानों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए बताया कि यदि सहकारी संस्थान अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें, तो किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है। धान की खरीदी के बाद उसका संग्रहण एक महत्वपूर्ण चरण होता है। राज्य में कई बार गोदामों की कमी और संग्रहण प्रक्रिया में लापरवाही देखी जाती है, जिससे धान की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस समस्या को हल करने के लिए सहकारी संस्थानों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।

2. साहित्य की समीक्षा

नीचे दिए गए अनुसंधानों को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की भूमिका के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जो धान की खरीदी, संग्रहण, संसाधन उपयोग दक्षता, और किसानों को मिलने वाले लाभों से संबंधित हैं।

समीक्षात्मक अध्ययन सारणी

लेखक	कार्य का विवरण	मुख्य निष्कर्ष
एग्रे एट अल. (2010)	पूर्वी अफ्रीका में विनिर्माण फर्मों के आकार और तकनीकी दक्षता का अध्ययन	तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए संसाधनों का कुशल उपयोग आवश्यक

अर्देशना और हंट (2011)	गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रमुख फसलों में उर्वरक उपयोग में अंतर का अध्ययन	उर्वरक उपयोग की असमानता किसानों की आय और उत्पादन लागत को प्रभावित करती है
दुबे (2007)	राष्ट्रीयकृत बैंकों और लघु-कुटीर उद्योगों की भूमिका का विश्लेषण	कृषि क्षेत्र में सहकारी संस्थानों और बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण
इंद्रनील एट अल. (2009)	पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में सीमांत और छोटे किसानों के उर्वरक उपयोग का अध्ययन	छोटे किसानों को उर्वरक और अन्य कृषि संसाधनों तक समान पहुंच नहीं मिलती
कुमार एवं अलगुमणि (2005)	तमिलनाडु के भवानी परियोजना क्षेत्र में धान उत्पादन की संसाधन उपयोग दक्षता का अध्ययन	बेहतर संसाधन प्रबंधन से धान उत्पादन में वृद्धि संभव
महाजन (2011)	बैंकिंग व्यवसाय के सिद्धांतों का अध्ययन	सहकारी बैंकों की नीतियां किसानों के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करती हैं
सिंह और फ़ज़ल (1998)	कृषि और ग्रामीण विकास के पहलुओं का अध्ययन	सहकारी संस्थानों का विस्तार कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है
सिंह और नासिर (2003)	बिहार में कृषि ऋण प्रवाह का आर्थिक विश्लेषण	कृषि ऋण प्रवाह में असमानता किसानों की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है
उदय कुमार एट अल. (2010)	कर्नाटक के कोप्पल जिले में धान उत्पादन में कीटनाशकों के उपयोग की दक्षता का अध्ययन	कीटनाशकों और अन्य संसाधनों के सही उपयोग से कृषि उत्पादन लागत कम हो सकती है

इस साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि धान की खरीदी एवं संग्रहण में सहकारी संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषि उत्पादन में संसाधन उपयोग की दक्षता बढ़ाने, उर्वरक एवं कीटनाशकों के प्रभावी उपयोग, तथा सहकारी बैंकों और सरकारी योजनाओं की सहायता से किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को धान खरीद एवं भंडारण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सहकारी संस्थानों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके।

3. उद्देश्य

1. रायपुर जिले में CG MARKFED द्वारा धान की खरीदी एवं संग्रहण प्रक्रिया का अध्ययन करना।
2. धान खरीदी एवं संग्रहण में आने वाली समस्याओं की पहचान कर समाधान सुझाना।

4. शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णात्मक (Descriptive) और तथ्यात्मक (Empirical) अनुसंधान विधियों पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक डेटा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत रायपुर जिले में धान की खरीदी एवं संग्रहण प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया, जिसके लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र किया गया। प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए सर्वेक्षण और साक्षात्कार विधियों का उपयोग किया गया। रायपुर जिले के 50 किसानों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), धान बिक्री प्रक्रिया, भुगतान प्रणाली, और CG MARKFED द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में प्रश्न पूछे गए। इसके अतिरिक्त, CG MARKFED अधिकारियों के साथ चर्चा की गई, जिसमें धान की खरीद, संग्रहण, और वितरण प्रणाली की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया गया। साथ ही, जिले के धान खरीदी केंद्रों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया, जिससे खरीद प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक समस्याओं और उनके समाधान की संभावनाओं को समझा जा सके। द्वितीयक डेटा के स्रोतों में छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि एवं सहकारी विपणन विभाग की रिपोर्टें, CG MARKFED की वार्षिक रिपोर्ट (2010-2011), और संबंधित शोध पत्र एवं पुस्तकें शामिल हैं। इन दस्तावेजों से धान खरीद प्रणाली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सरकारी नीतियाँ, और पूर्व के अध्ययन प्राप्त हुए, जो इस शोध को सटीकता प्रदान करते हैं। संग्रहित डेटा का सांख्यिकीय उपकरणों की सहायता से विश्लेषण किया गया, जिससे धान खरीदी प्रक्रिया की प्रवृत्तियों और उसमें संभावित सुधारों को समझने में सहायता मिली।

5. परिणाम एवं चर्चा

तालिका 1 में वर्ष 2010 और 2011 के दौरान रायपुर जिले में धान की खरीदी मात्रा और इससे लाभान्वित किसानों की संख्या का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2010 में 15,00,000 टन धान की खरीदी की गई थी, जो अगले वर्ष बढ़कर 16,50,000 टन हो गई, अर्थात् कुल 10% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में, धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या 8,00,000 से बढ़कर 8,20,000 हो गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिक किसान सरकारी खरीद प्रणाली से जुड़ रहे हैं।

तालिका 1 धान खरीदी की मात्रा (2010-2011)

वर्ष	धान खरीदी (टन में)	कुल किसानों की संख्या
2010	15,00,000	8,00,000
2011	16,50,000	8,20,000

इस वृद्धि का एक मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (CG MARKFED) द्वारा अपनाई गई प्रभावी नीतियाँ रही हैं, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि और अधिक खरीद केंद्रों की स्थापना शामिल है। यह दर्शाता है कि सरकारी खरीद प्रणाली किसानों के लिए अधिक आकर्षक बनी, जिससे उन्होंने औपचारिक विपणन चैनलों को प्राथमिकता दी। हालांकि, खरीद में यह वृद्धि संग्रहण प्रणाली पर दबाव बढ़ा सकती है। यदि गोदामों की क्षमता इस अनुपात में नहीं बढ़ी, तो भविष्य में भंडारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः नीति निर्माताओं को इस दिशा में ठोस उपाय करने की आवश्यकता है ताकि खरीदी गई उपज का समुचित भंडारण एवं प्रबंधन किया जा सके।

तालिका 2 न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

वर्ष	MSP (₹ प्रति क्विंटल)
2010	1000
2011	1030

तालिका 2 के अनुसार, वर्ष 2010 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹1000 प्रति क्विंटल था, जो 2011 में ₹1030 प्रति क्विंटल हो गया, अर्थात् 3% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि किसानों की आय में सुधार लाने और उन्हें उचित मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। MSP में यह वृद्धि किसानों को सरकारी खरीद प्रणाली की ओर आकर्षित करने में सहायक रही, जिससे अधिक किसानों ने अपनी उपज सरकारी एजेंसियों को बेची, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही।

तालिका 3 संग्रहण क्षमता

वर्ष	संग्रहण क्षमता (टन में)
2010	8,00,000
2011	9,00,000

तालिका 3 के अनुसार, रायपुर जिले में धान की संग्रहण क्षमता वर्ष 2010 में 8,00,000 टन थी, जो 2011 में 9,00,000 टन हो गई, अर्थात् 12.5% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि CG MARKFED द्वारा संग्रहण सुविधाओं के विस्तार और नई गोदाम इकाइयों की स्थापना का परिणाम हो सकती है। हालांकि, इसी अवधि में धान की खरीदी 10% बढ़ी, जो संग्रहण क्षमता वृद्धि के लगभग समान अनुपात में है। यह संकेत करता है कि भंडारण व्यवस्था में सुधार किए बिना भविष्य में अधिक खरीद प्रबंधन कठिन हो सकता है।

तालिका 4 भुगतान समय

वर्ष	भुगतान अवधि (दिनों में)
2010	20
2011	15

तालिका 4 के अनुसार, वर्ष 2010 में किसानों को धान बिक्री के बाद भुगतान प्राप्त करने में औसतन 20 दिन लगते थे, जो 2011 में घटकर 15 दिन हो गया, अर्थात् 25% की कमी दर्ज की गई। भुगतान अवधि में इस सुधार का कारण सरकार द्वारा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाना हो सकता है। भुगतान में तेजी आने से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, जिससे वे अगली फसल की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह सुधार किसानों में सरकारी खरीद प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ाने में सहायक रहा।

तालिका 5 किसान संतोष स्तर

स्तर	2010 (%)	2011 (%)
संतुष्ट	70	80
असंतुष्ट	30	20

तालिका 5 के अनुसार, वर्ष 2010 में 70% किसान सरकारी धान खरीदी व्यवस्था से संतुष्ट थे, जबकि 2011 में यह बढ़कर 80% हो गया, यानी 10% की वृद्धि हुई। वहीं, असंतुष्ट किसानों का प्रतिशत 30% से घटकर 20% हो गया, जो दर्शाता है कि CG MARKFED की नीतियों और सेवाओं में सुधार हुआ। यह संतोष स्तर बढ़ने का मुख्य कारण MSP में वृद्धि, संग्रहण क्षमता में सुधार और भुगतान प्रक्रिया में तेजी हो सकता है। यह सकारात्मक प्रवृत्ति किसानों की सरकारी खरीद प्रणाली में बढ़ती रुचि को दर्शाती है।

6. निष्कर्ष

इस अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (CG MARKFED) द्वारा धान की खरीदी एवं संग्रहण प्रक्रिया में सुधार हुआ है, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ। धान खरीदी की मात्रा 2010 में 15,00,000 टन से बढ़कर 2011 में 16,50,000 टन हो गई, जिससे अधिक किसानों को सरकारी खरीद प्रणाली का लाभ मिला। इसी अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹1000 से बढ़कर ₹1030 प्रति क्विंटल हो गया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई और वे औपचारिक विपणन प्रणाली की ओर आकर्षित हुए। इसके अलावा, धान संग्रहण क्षमता में 12.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे खरीदी गई उपज के भंडारण की बेहतर व्यवस्था संभव हो सकी। हालांकि, बढ़ती खरीदी के अनुपात में संग्रहण सुविधाओं का विस्तार अपर्याप्त हो सकता है, जिससे भविष्य में भंडारण से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं, किसानों को भुगतान प्राप्त करने की अवधि 20 दिन से घटकर 15 दिन हो गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और कृषि कार्यों की निरंतरता बनी रही। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसान संतोष स्तर 70% से बढ़कर 80% हो गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि CG MARKFED की नीतियाँ और सेवाएँ अधिक प्रभावी हो रही हैं। हालाँकि, कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कि संग्रहण क्षमता में और वृद्धि, भुगतान प्रक्रिया को और अधिक तेज बनाना, तथा खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाना। सरकार और सहकारी संस्थानों को इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर नीतिगत सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे यह प्रक्रिया किसानों के लिए अधिक सुविधाजनक और लाभकारी बन सके।

भविष्य की संभावनाएँ

1. बढ़ती धान खरीदी को ध्यान में रखते हुए गोदामों की क्षमता का विस्तार और आधुनिक भंडारण तकनीकों (जैसे साइलो स्टोरेज) को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में भंडारण संबंधी समस्याएँ न हों।
2. किसानों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान अवधि को 10 दिनों या उससे कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे वे अपनी कृषि जरूरतों को बिना किसी वित्तीय बाधा के पूरा कर सकें।
3. रायपुर जिले में अधिक धान खरीदी केंद्रों की स्थापना से किसानों को परिवहन लागत में राहत मिलेगी और सरकारी खरीद प्रणाली तक उनकी आसान पहुँच सुनिश्चित होगी।
4. धान खरीदी, संग्रहण, और भुगतान प्रक्रिया के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा सकता है, जिससे किसानों को अपने भुगतान और उपज की स्थिति की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके।
5. CG MARKFED को धान प्रसंस्करण, निर्यात, और मूल्य संवर्धन जैसी रणनीतियों को अपनाना चाहिए, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

संदर्भ

1. एग्री, एन., लुवांडा, ई., और शितुंडु, जे. (2010) पूर्वी अफ्रीकी विनिर्माण फर्मों में फर्म का आकार और तकनीकी दक्षता। करेंट रिसर्च जर्नल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, 2(2), 69-75।

2. अर्देशना, एन. जे., और खुंट, के. ए. (2011) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रमुख चयनित फसलों के बीच उर्वरक उपयोग में अंतर और इसके निर्धारक। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, 2(1), 1-6।

3. दुबे, ए. (2007) राष्ट्रीयकृत बैंक और लघु-कुटीर उद्योग। वैभव प्रकाशन।
4. इंद्रनील, डी., बिस्वजीत, जी., और साहू, एन. सी. (2009) पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुछ चयनित क्षेत्रों में सीमांत और छोटे किसानों के बीच उर्वरक उपयोग परिदृश्य। इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर्स, 5(10), 45-57।
5. कुमार, सी.एस., और अलगुमानी, टी. (2005) तमिलनाडु में निचले भवानी परियोजना कमान क्षेत्र में धान की संसाधन उपयोग दक्षता। भारतीय कृषि अर्थशास्त्र पत्रिका, 60(3), 515।
6. महाजन, एम. (2011) बैंकिंग व्यवसाय के सिद्धांत। निराली प्रकाशन।
7. सिंह, ए.एल., और फजल, एस. (1998) कृषि और ग्रामीण विकास। बी.आर. प्रकाशन निगम।
8. सिंह, एस.के.पी., और नासिर, एस. (2003) बिहार में कृषि ऋण प्रवाह: एक आर्थिक विश्लेषण। भारतीय कृषि अर्थशास्त्र पत्रिका, 58(1), 137-145।
9. उदयकुमार, एच., बसवराज, एच., और गुलेदगुड्डा, एस.एस. (2010) कर्नाटक के कोप्पल जिले में धान उत्पादन में कीटनाशकों की लागत, रिटर्न और संसाधन उपयोग दक्षता। भारत में कृषि स्थिति, 67(4), 189-195।